दिवाली की रात पिटा थानेदार, आखिर क्यों ?

फ़रीदाबाद (म. मो.) थाना एसजीएम नगर की चौकी एनएच तीन के एएसआई जमील खान को 19-20 की मध्य रात्रि में 12 लड़कों ने इतना बुरी तरह से पीटा कि उसे 5 दिनों तक बीके अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसका कसूर यह था। कि रात करीब 12 बजे उसने इन लड़कों को एक चौक के पास बैठ कर शराब पीते व पटाखे चलाते देख हिदायत दी कि रात बहुत हो गई है, अपने अपने घरों को चले जाओ।

करीब दो बजे गश्त करते हुए तीन जनों की पुलिस पार्टी पुन; जब उसी स्थान पर पहुंची तो वही लड़के अभी भी शराब पीकर हुड़दंग करते पटाखे चला रहे थे। एएसआई जमील ने जिप्सी से उतर कर जब पुन; इन्हें रोका - टोका तो एक ने शराब की बोतल एएसआई के माथे पर इतनी जोर से मारी कि उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर फिर पड़ा।

फिर पड़े इस एएसआई को इन लड़कों ने ठोकरों व डंडों से बुरी तरह पीटा। इस बीच एक सिपाही तो जिप्सी से कूद कर भाग गया लेकिन ड्राइवर को भागने का मौका न देते हुए लड़कों ने दबोच लिया और जी भर के पीटा। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब तक और पुलिस बल आया तब तक ये लड़के मौके से फरार हो गए। पुलिस ने भ.द.स. की धारा 332, 353, 307, 148, 149, 185 व 188 आदि के तहत मुकदमा न. 624 दर्ज कर लिया।

26 अक्टूबर तक उक्त 12 में से पांच को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया हैं और बाकियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार करके जेल काटने भेज दिया जाएगा, यह तो तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस पर इस तरह के प्राण घातक हमला करने की हिम्मत किसी में भी आती कहां से है ? और इस तरह के हमले अब आए दिन होने लगे है। इसी सप्ताह थाना सारन के एक सिपाही को भी डबुआ सब्जी मंडी के निकट पीटा गया था।

दरअसल मौजूदा राजनीतिक एवं आपराधिक न्याय व्यवस्था के चलते केवल शरीफ आदमी ही पुलिस एवं कानून से डरते है। अपराधी और लफंटर न कानून की परवाह करता है न पुलिस की। आए दिन अपराध करने वाला जानता है कि पुलिस एवं कानून से कैसे निपटा जाता है।

इलाके के राजनेताओं से उसके घनिष्ठ संबंध होते हैं जैसे कि टंडन के विधायक सीमा त्रिखा से। इसके अलावा पुलिस वालों से लेन देन करना भी वह सीख चुका होता है। इसके चलते निर्दोष शिकायतकर्ता तो थाने में हाथ जोड़े खड़ा रहता है और दोषी थानेदार के सामने कुर्सी पर बैठ कर चाय पी रहा होता है।

मौजूदा मामले में भी मुख्य आरोपी मनीष, जिसका एनएच तीन में ईव वीयर के नाम से शोरूम है, सीमा त्रिखा के पास पहुंचा था। उसे पूरा भरोसा था कि सीमा उसे बचा लेगी। हालांकि फिलहाल सीमा ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं।

बेमिसाल भाजपाई तानाशाही: पत्रकार व दुकानदार की गिरफ्तारी, 'मर्सल' पर कैंची और राजस्थान का काला कानून

-रज्जन सैमोयूकि

अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के खिलाफ जब वहां का पूरा मीडिया उठकर खड़ा हो गया है तो भारत में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, काला कानून लाया जा रहा है, फिल्मों से सीन हटाए जा रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले गढ़े जा रहे हैं...और जनता चैन की नींद सो रही है। जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था...यह कहावत अब भारत के संदर्भ में उल्टी हो गई है। ...भारत जब जल रहा है तो जनता चैन की नींद सो रही है।

हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटीं, उस पर नजर डालिए...

1. भाजपा के खिलाफ लगातार लिखने वाले और छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की सेक्स सीडी बनाने वाले पत्रकार विनोद वर्मा को गाजियाबाद स्थित उनके घर से चार दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया।

2. तमिल में बनी फिल्म मर्सल से नोटबंदी और जीएसटी पर की गई टिप्पणी को निकालने के लिए भाजपा ने कहा। केंद्र सरकार ने मर्सल फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर के घर छापा डलवाया। फिल्म निर्माता ने वह टिप्पणी फिल्म से हटा दी।

3. भाजपा शासित राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार ने एक बिल विधानसभा में पारित कराने का प्रयास किया, जिसके तहत भ्रष्टाचार व अन्य मामलों में किसी भी सरकारी अफसर, जज के खिलाफ बिना सरकार की अनुमति के न तो जांच की जा सकेगी और न केस दर्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा मीडिया इस बारे में किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा। मीडिया पर इस कानून के तहत और भी बंदिशें लगाने का प्रस्ताव लाया गया। यह बिल अभी पास होना है।

4. गुजरात पुलिस ने एक अस्पताल में कार्यरत दो मुस्लिम युवकों को यह कहकर उठाया कि ये लोग आईएस में जाने वाले थे और आतंकी गतिविधियों में कथित तौर पर लिप्त हैं। फिर बताया गया कि इस अस्पताल के ट्रस्टी 2014 तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल रहे हैं। इसलिए पटेल के खिलाफ जांच होनी चाहिए। भाजपा ने यह मांग कर डाली। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में हारने की डर से वह कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसी चाल चल रही है।

पत्रकार पर फर्जी आरोप

पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी करते समय छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि प्रकाश बजाज नामक शख्स की शिकायत पर गिरफ्तारी की गई। जिसमें कहा गया कि विनोद वर्मा के पास कुछ पोर्न सीडी है और वह छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आजकल पत्रकारिता इतनी घटिया दौर में है कि ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाना सबसे आसान है और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन गिरफ्तारी के समय ही पत्रकार विनोद वर्मा ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की सेक्स सीडी है और यह सीडी सिर्फ उन्हीं के पास नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सारे पत्रकारों के पास है। यह पब्लिक डोमेन में भी है। चूंकि वह केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

विनोद वर्मा बीबीसी के संवाददाता रह चुके हैं। इसके अलावा वह अमर उजाला में भी काम कर चुके हैं। उनकी छवि शुरु से एक साफ सुथरे पत्रकार की रही है। किसी को छत्तीसगढ़ पुलिस की गढ़ी हुई कहानी में दम नजर नहीं आया। लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में रंगरेलियां मनाने वाला मंत्री राजेश मूणत की सेक्स सीडी बन चुकी है। चूंकि उसकी आंच रमन सिंह तक भी पहुंचेगी, इसलिए फौरन कार्रवाई की गई। रमन सिंह तक इसकी आंच आने की संभावना इसलिए बनी, क्योंकि यह मंत्री मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक और खास है। ऐसा हो नहीं सकता कि गुप्तचर विभाग (सीआईडी) खुद संभालने वाले रमन सिंह को इस मंत्री की करतूतों की जानकारी न हो।

गिरफ्तारी से उठे सवाल

क्या खबर के लिए पाई गई एक सेक्स क्लिप के होने के चलते पत्रकार को गिरफ्तार करना न्यायसंगत है ?

सेक्स क्लिप तो मंत्री के खिलाफ सबूत के तौर पर काफी पुख्ता मानी जाएगी, जबकि रंगदारी वसूलने का मंत्री का आरोप जबानी है। एक सबूत जो सामने है उसको दरकिनार करते हुए जबानी आरोप पर पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस मामले में इतनी ही जल्दी थी तो मंत्री राजेश मूणत को हिरासत में लेकर उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई ?

आम जनता की रिपोर्ट तक न दर्ज करने वाली पुलिस की सक्रियता देखिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस हजारों किलोमीटर का सफर कर रात के अंधेरे में गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंच गई।

भाजपा में कुछ नेताओं ने जब दबी जबान से रमन सिंह सरकार के इस एक्शन पर विरोध हुआ तो रमन सिंह को इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि केस अदालत में जाने पर यह पूछा जाएगा कि पत्रकार की गिरफ्तारी तो ठीक है लेकिन सीडी की जांच का आदेश क्यों नहीं हुआ। इससे बचने की तैयारी पहले से ही कर ली गई है।

रमन सिंह कितने दिन के मेहमान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके बेटे का नाम पनामा पेपर्स स्कैंडल में आ चुका है। रमन सिंह की सरकार के तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों के नरसंहार के लिए पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों को खुली छूट देने का आरोप भी रमन सिंह की सरकार पर है। आदिवासियों की जमीन, जंगल, खनिज पदार्थों को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने की नीति पर चलने वाले रमन सिंह के खिलाफ भाजपा में एक खेमा सक्रिय है। बताया जाता है कि रमन सिंह के खास मंत्री की सीडी बनवाने में उसी खेमे ने बड़ी भूमिका निभाई है। देखना यह है कि भाजपा आलाकमान और आरएसएस रमन सिंह को कुर्सी पर कितने दिनों तक बनाए रखता है।

दुकानदार को भी जेल भेजा

पलवल के पास एक गांव है बागपुर। इस गांव में नरेश अपनी दुकान चलाता है। अभी तक उसे कोई नहीं जानता था लेकिन एक दिन उसने मोदी को गाली क्या दी कि वह रातोरात मशहूर हो गया। नरेश को दिवाली से पहले चांदहट थाने की पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जब वह

शेष पेज चार पर

पुलिस की रिश्वतखोरी व एनएचएआई की लापरवाही ने ले ली दो जान

मज़दूर मोर्चा

फ़रीदाबाद। एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए पुलो को तो लोगों के इस्तेमाल के लिए चालू कर दिया। लेकिन पुलों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने की जरूरत महसूस नहीं की। जिसका खामियाजा बल्लभगढ़ की भगत सिंह कालोनी में रहने वाले किशोर आशिफ व पप्पू को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दुर्घटना में आशिफ का भाई फैजान भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। दुर्घटना के दो मुख्य कारण पुल पर स्ट्रीट लाइट का न होना और कानून का उल्लंघन करके चलने वाला अवैध ट्रैक्टर ट्राला है

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना का यह न तो पहला मामला है और न आखिरी। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है लोग मरते रहते है लेकिन सरकार की किसी भी एजेंसी के कान पर जूं तक नहीं रैगती। स्ट्रीट लाइटों की कमी और एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) न होने कारण लोगों को आए दिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है।

एनएचएआई ने फ़रीदाबाद शहर से गुजर रहे करीब 12 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को सिक्स लैन का बना कर कई फ्लाईओवर का निर्माण कर उन्हें लोगों के इस्तेमाल के लिए चालू भी कर दिया। लेकिन लापरवाही बरतते हुए इन पुलों पर एनएचएआई ने स्ट्रीट लाइटें लगवाने की जरूरत महसूस नहीं की।

एनएचएआई की लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं है। फ़रीदाबाद शहर से गुजरने वाले करीब 12 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहीं भी फुट ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत भी महसूस नहीं की गई। 12 किलोमीटर के इस रास्ते पर वाहनों के तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए छह फ्लाईओवर तो बना कर तैयार कर दिए गए है। लेकिन कहीं भी पैदल यात्रियों के लिए फुटओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं बनाया गया।

हालांकि मेट्रो स्टेशनों पर एफओबी हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को मैगपाई चौक पर सड़क पार करनी है तो उसे ओल्ड फ़रीदाबाद मेट्रो स्टेशन या फिर नीलम अजरौंदा तक पैदल जाना पड़ेगा। यह पैदल चलने वाले लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एफओबी बनाने के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच डिवाइडर पर ग्रील लगाना बेहद जरूरी है।

सुबह शाम फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर भारी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं। अधिकतर मज़दूर या तो साइकिल से चलते हैं या फिर पैदल। इन लोगों के लिए सड़क पार करने के सुरक्षित स्थान और साधन बनाया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले हादसे बढ़ते चले जाएंगे। इस सड़क पर दस नंबर भट्ठा, मेवला महाराजपुर मोड़, मैग्पाई चौक, मुजेसर फाटक, गुडईयर और अजरौंदा चौक के पास एफओबी या अंडरपास बनना बहुत जरूरी है, यदि ऐसा नहीं हो तो कम से कम संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग और रेड लाइटों की व्यवस्था तो जरूर की जानी चाहिए।

इसके अलावा मुजेसर मोड़ सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान है, क्योंकि मुजेसर फाटक से हर रोज करीब 25 से 30 हजार कर्मचारी, फैक्ट्री मजदूर, विद्यार्थी आदि गुजर कर राष्ट्रीय राजमार्ग के इस मोड़ की ओर आते जाते हैं। शाम को छह बजे के बाद फैक्ट्रियों से छूटने के बाद मजदूर अक्सर अंधेरे में वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए इस स्थान पर स्ट्रीट लाइट, रेड लाइट और संकेतक बहुत जरूरी हैं।

दूसरी तरफ पुलिस की रिश्वतखोरी के कारण भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है। ट्रैक्टर ट्राली और सड़कों पर चलने वाले अन्य अवैध वाहनों के चालक चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को रिश्वत देकर बेखौंफ दौड़ते है। पुलिस अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान चला कर इन्हें बंद करने के दावे आए दिन करती रहती है। लेकिन इसके बावजूद शहर के किसी भी हिस्से में इन अवैध वाहनों को दौड़ते देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मचारियों की इस रिश्वतखोरी का बड़े अधिकारियों को पता नहीं है। सबकुछ जानते हुए भी ये लोग आंखे मूंदे बैठे है।

मामा श्री ही क्या बाकी विधायक भी पीछे नहीं

पेज एक का शेष

थोड़ी थोड़ी बानगी अन्य विधायकों की भी जाननी जरूरी है। अतिविश्वासनीय जानकारों के अनुसार थाना सेन्ट्रल व सेक्टर सात उद्योगमंत्री विपुल गोयल के खाते में जरूर है। लेकिन यहां किसी बड़े घाल मेल की शिकायत नहीं है।

थाना छांयसा टेकचंद व मूलचंद के खाते में है। बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीतने वाले टेकचंद को भाजपा सरकार की गोद में आकर सिर्फ इसलिए बैठना पड़ा कि थोड़ी बहुत दुकानदारी उसकी भी चल पाए।

थाना सारन नागेद्र के खाते में है। वे भी चौटाला पार्टी के विधायक होने के बावजूद मनोहर सरकार के दुमछल्ले केवल इसलिए बने हुए है, ताकि पुलिस वाले उन्हें भी सलाम बजाते रहें। चर्चा काफी गर्म है कि पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर ने यहां तैनाती पाने के लिए पूरे दो लाख खर्चे थे। लेकिन महीने भर में ही चलता कर दिया गया।

थाना एनआईटी और एनएच तीन की चौकी विधायक सीमा त्रिखा के खाते में है। सीमा ने यह इलाका अपने तथाकथित चाचा तनेंद्र टंडन के हवाले कर रखा है। जिसकी लूट खसौट का विवरण इस पत्र में लगातार प्रकाशित होता आ रहा है।

आश्चार्य कि बिगड़े माहौल में भी दो चार एसएचओ है जो खुलेआम कहते कि उन्हें थाने की तैनाती का कोई शौक नहीं, पुलिस लाइन में जाने को तैयार है, काम करेंगे तो अपनी कानूनी समझ से करेंगे, किसी नेता के इशारे पर नहीं।